

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री नीरज मिश्र आर.प.परा.

राजस्व आवेदन संख्या :- 222/2019

प्रार्थीगण

बनाम

विप्राथीगण

1 पुष्पा पुत्री भंवरलाल पत्नी सम्पतराज जैन निवासी भाड़खा हाल निवासी खागल गीहल्सा बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर
2 मीना पुत्री भंवरलाल पत्नी पुखराज जैन जाति जैन निवासी भाड़खा हाल रणधा तहसील फतेहगढ तहसील जिला जैसलमेर
3 रेखा पुत्री भंवरलाल पत्नी सम्पतराज जैन जाति ओरावाल निवासी भाड़खा हाल निवासी झाख तहसील गिडा जिला बाड़मेर।

1 अशोक कुमार 2 मदन पिसारान भंवरलाल 3 मगुदेवी पत्नी भंवरलाल 4 मदन 5 गीतम 6 सुरेश 7 बत्तागीदेवी पिसारान चिन्तामणदास 8 मोहिनीदेवी पत्नी चिन्तामणदास 9 बबुदेवी पत्नी केशरीमल 10 बंकीदास 11 कमला पिसारान केशरीमल जाति ओरावाल निवासी भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर 12 सुशीलादेवी पत्नी ओमप्रकाश 13 राजेश मेहता 14 कैलाश मेहता पिसारान ओमप्रकाश जाति माहेश्वरी निवासी रटेशन रोड बाड़मेर 15 जयप्रकाश पुत्र बन्नाराम जाति सिन्धी लोहाणा निवासी सरदारपुरा बाड़मेर 16 सवाईलाल पुत्र स्वरूपचन्द जाति दर्जी निवासी सरदारपुरा बाड़मेर 17 स्वरूपचन्द पुत्र भगाराम जाति दर्जी निवासी सरदारपुरा बाड़मेर 18 बन्नाराम पुत्र गुरूनामल जाति सिन्धी निवासी सरदारपुरा बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर 19 सुशीलादेवी पत्नी भोगराज बोहरा 20 भीमराज पुत्र सोनराज बोहरा जाति जैन निवासी द्वारकापुरी सी रकीम जयपुर।

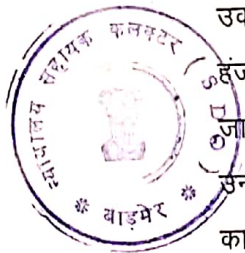
राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RTA Act.

उपस्थिति :- 1 श्री राणाराम गौड़, वकील प्रार्थीगण।
2 श्री रमेश सोलंकी, वकील अप्रार्थी संख्या 12 से 14।

निर्णय

दिनांक 2-01-09/19

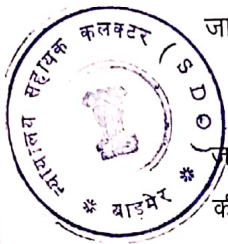
संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी संभावना है। प्रार्थीगण द्वारा एक ओवदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भाड़खा पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील बाड़मेर के खसरा संख्या 16 रकबा 23.13 बीघा (नये खसरा संख्या 262/16 व 264/16 रकबा क्रमशः 09.07 बीघा एवं 09.06 बीघा, खसरा संख्या 261/16, 263/16 रकबा क्रमशः 02.10 बीघा व 02.10 बीघा, खसरा संख्या 317 रकबा 25.01 बीघा कुल रकबा 48.14 बीघा) आए हुए है। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण एवं विप्राथी संख्या 01 से 11 के दादा मुतवफी हंजारीमल के स्वामित्व एवं आधिपत्य का होने के कारण पर्चा लगान उनके नाम से जारी किया गया। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के दादा हंजारीमल का 1/2 हिस्सा व उनके भाई केसरीमल का भी 1/2 हिस्सा वक्त बन्दोबस्त दर्ज हुआ था। हंजारीमल का देहान्त होने पर वादग्रस्त खेतों की भूमि प्रार्थीगण के पिता मुतवफी भंवरलाल एवं ताऊ चिन्तामणदास की खातेदारी में अंकित हो गई। तत्पश्चात प्रार्थीगण के पिता



भंवरलाल का देहान्त सन् 2002 में हो गया। भंवरलाल के देहान्त के पश्चात विधि सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

विधि में किये संशोधन के पश्चात विवाहित पुत्रियों को भी सहदायिक मानने का प्रावधान जोड़ा गया है। इसके तहत भी 2005 से पूर्व में किसी कर्ता अर्थात भंवरलाल के स्वर्गवास के पश्चात परिवार की सम्पतियों के पुत्र सहदायिकों में न्यस्त होने के पश्चात उक्त संशोधन के आधार पर प्रार्थनीगण विवाहित पुत्रियों को संशोधन के पश्चात ही सहदायिकी की प्राप्ति प्राप्त होती है। इसलिए स्वर्गीय भंवरलाल के 2002 में स्वर्गवास के पश्चात उसके संयुक्त परिवार की पैतृक वादग्रस्त भूमि में प्रार्थनीगण विवाहित पुत्रियों के सहदायिक नही होने से विवेच्य विक्रय पत्रों को चुनौति देने अथवा अमान्य करने का प्रार्थनीगण का वाद व आवेदन प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सितम्बर 2005 में हुए बन्टवाड़ान्यस्त भूमियों की स्थिति में नये संशोधन को लागू नही होना निर्णित किया है। स्वर्गीय भंवरलाल के पैतृक संयुक्त हिन्दु परिवार के खातेदारी की अन्य भूमि मौजा भाड़खा में खसरा संख्या 317 की आई हुई है, जो सहदायिक अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के नाम दर्ज है। प्रार्थनीगण ने इन खसरों की भूमि में अपना हक नही मांग कर अप्रार्थी संख्या 12 से 14 को बेची हुई भूमि को दुराशय से अनाधिकृत रूप से चुनौति देकर वाद प्रस्तुत किया हैं, जो खारिज योग्य है। यदि प्रार्थनीगण का वादग्रस्त भूमि में हक-हिस्सा बनता है तो भी वह खसरा संख्या 317 की भूमि से प्राप्त किया जा सकता है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थनीगण का कभी भी कब्जा काशत नही रहा है। उक्त भूमि पर कब्जा काशत अप्रार्थी संख्या 01 से 03 का है। प्रार्थनीगण अपने ससुराल में रहती है। इसलिए उन्हे बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अप्रार्थी संख्या 12 से 14 का वादग्रस्त भूमि पर खरीद से आज तक कब्जा काशत है। लिहाजा प्रार्थनीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नही होगी। आवेदन खारिज योग्य है।

वकील प्रार्थनीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 12 से 14 की और से प्रस्तुत जवाब का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 12 से 14 द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10.06.2019 को अपाशत करने का निवेदन किया है, जबकि उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 12 से 14 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का उल्लेख किया गया है, जो विधि अनुसार प्रार्थना पत्र में नही किया जा सकता है। प्रार्थनीगण द्वारा प्रस्तुत वाद साक्ष्य सबूत के आधार पर विनिश्चित किया जा सकेगा।



उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थनीगण द्वारा आवेदन में तथा जवाबुलजवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थनीगण भंवरलाल की प्रथम श्रेणी की वारिसान होने से भंवरलाल की मृत्यु पर उसके नाम से नामान्तरण पारित किया जाना चाहिए था। ऐसा न कर कानूनी भूल की है। प्रार्थनीगण वादग्रस्त भूमि में जन्म से हिस्सा निहित है। प्रार्थनीगण को उसके कब्जे (S.D.O.) काशत से बेदखल किया जाता है तो प्रार्थनीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया

प्रकरण प्रार्थनी के पक्ष में है। लिहाजा प्रार्थनीगण के पक्ष में वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

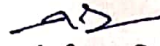
वकील अप्रार्थी संख्या 12 से 14 की और से आवेदन के जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि भंवरलाल की मृत्यु 2002 में होने के पश्चात वादग्रस्त भूमि अविभक्त हिन्दू परिवार की पैतृक भूमि होने से उनके संयुक्त परिवार के सहदायिकों प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के नाम नामान्तरित सही की गई। विवाहित पुत्रियों को कानूनन सहदायिकी नहीं माना गया है। सितम्बर 2005 को हिन्दू विधि में किये गये संशोधन के पश्चात विवाहित पुत्रियों को भी सहदायिक मानने का प्रावधान जोड़ा गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी सितम्बर 2005 में अपने निर्णय में उक्त तथ्य को भंलीभांती परिभाषित किया है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थनीगण का कब्जा काशत नहीं है। लिहाजा उन्हें बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 12 से 14 वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार है, जिसके विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थनीगण अधिकारी नहीं है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थनीगण के पक्ष में नहीं है और न ही सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णाय क्षति के बिन्दु प्रार्थनीगण के पक्ष में है। आवेदन खारिज योग्य है।


हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 12 से 14 द्वारा अभिलिखित खातेदारान से क्रय की गई है और उनके पक्ष में खातेदारी इन्द्राज भी हो चुके है। संलग्न विक्रय पत्र के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि पर क्रेता अप्रार्थी संख्या 12 से 14 का कब्जा है। न्याय के मतानुसार कब्जा धारण किये हुए अभिलिखित खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 12 से 14 जो इस भूमि के क्रेता है, राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज है तथा प्रथम दृष्टया भूमि पर कब्जा अप्रार्थी संख्या 12 से 14 का ही होना पाया गया है। प्रार्थनीगण को इस वादग्रस्त भूमि में जन्मजात खातेदारी अधिकार प्राप्त है अथवा नहीं यह बिन्दु मूल वाद से निर्धारित होगा। इस बिन्दु का निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन से नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रार्थनीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन अस्वीकार किया जाता है। उनके पक्ष में पारित अन्तरिम निषेधाज्ञा दिनांक 10.06.2019 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय आज दिनांक 20.08.19 को सरें इजलास सुनाया गया।


(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर


उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर